

सत्यव्रत विश्वास एवं अन्य।

बनाम

कल्याण कुमार किस्कु एवं अन्य।

27 जनवरी, 1994

[एस. मोहन और डॉ. ए. एस. आनंद, जेजे।]

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971: प्रलोभन के खिलाफ कार्यवाही करने वाले न्यायालयों की शक्ति-अवमानना क्षेत्राधिकार के दायरे तक सीमित करना-विचार नहीं करना।

अभ्यास और प्रक्रिया: एक पक्ष द्वारा अदालत में मौखिक उल्लेख ने कार्यवाही में खुद को शामिल नहीं किया अदालत ने इस तरह के मौखिक आवेदन राशि पर आदेश दिया

प्रक्रिया के कानून को अलग करने के लिए इसलिए पदच्युत किया गया।

शब्द और वाक्यांश: यथास्थिति-का अर्थ।

'मैक्सिम' एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट-की प्रयोज्यता।

प्रथम प्रतिवादी ने चर्च की संपत्ति के संबंध में स्वामित्व की घोषणा के लिए उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। मुकदमे में यह दावा किया गया था कि डायोसिस में उक्त संपत्ति में तीन कमरे शामिल थे और

इसके कब्जे को बाधित नहीं किया जा सकता है। अंतर्वर्ती आवेदनों पर, 15 सितंबर, 1988 को यथास्थिति के आदेश सहित कुछ आदेश पारित किए गए थे। वादी ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक अवमानना याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया गया था क्योंकि अपीलकर्ताओं ने मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया था, पानी की आपूर्ति काट दी थी, सीवरेज लाइन को बाधित किया था और प्रतिवादियों को कमरों की मरम्मत कराने से रोक दिया था।

उच्च न्यायालय ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। उन्हें ताला तोड़ने और अपना ताला लगाने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, उक्त आदेश को इस प्रभाव से संशोधित किया गया कि प्राप्तकर्ता वस्तुओं की सूची बनाएगा, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार को ताला और चाबी के नीचे नहीं रखेगा। उक्त आदेश में इस आशय का संशोधन करने की मांग की गई थी कि विशेष अधिकारी को प्रत्येक पक्ष के प्रतिनिधियों को अनुमति देनी चाहिए और आक्रमण करने के समय कब्जा करने वाले में से किसी को भी अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 अर्थात् द बिल्डर्स 10 मई 1993 के समझौते के अनुसार, एक पूर्व किरायेदार के तहत एक उप-किरायेदार होने का दावा करते हुए, और किसी भी कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, और न ही खुद को इस तरह से शामिल किया, ताला हटाने के लिए मौखिक प्रार्थना की और अदालत ने इसकी अनुमति दी और प्राप्तकर्ता को हटाने का निर्देश दिया ताला।

उपर्युक्त कार्यवाहियों से व्यथित, एक अपील को प्राथमिकता दी गई थी डिवीजन बेंच को खारिज कर दिया गया था लेकिन अदालत को प्रथम दृष्टया संतुष्ट किया गया था कि बिल्डर विवादित परिसर पर कब्जा कर रहा था। इस प्रकार, न्यायालय ने बिल्डर को इस उद्देश्य के लिए उक्त परिसर पर कब्जा करने की अनुमति दी सामान्य रूप से व्यवसाय करना, और व्यवसाय शुल्क का भुगतान करना। न्यायालय द्वारा नियुक्त संयुक्त प्राप्तकर्ताओं को। इसलिए उनकी अपील है।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि यथास्थिति को देखते हुए 15 सितंबर, 1988 में कोई किरायेदारी या उप-किरायेदारी नहीं बनाई जा सकी, और यह अजीब बात थी कि बिल्डरों द्वारा एक मौखिक आवेदन किया गया था और अदालत ने उस पर एक आदेश पारित किया था।

प्रथम उत्तरदाता ने तर्क दिया कि यथास्थिति को देखते हुए न्यायालय द्वारा आदेशित, डायोसिस अपनी गतिविधियों को जारी रखने का हकदार था 20.5.1988 पर।

बिल्डरों ने तर्क दिया कि कोई कानूनी अक्षमता नहीं थी पूर्व किरायेदार की संपत्ति को उप-पट्टा देने के लिए और इसलिए बिल्डरों को कानूनी रूप से शामिल किया गया था और उन्हें विशेष अधिकारी द्वारा परेशान किया गया था जिसने ताला लगाया था, और उसके बाद ही अदालत के समक्ष एक मौखिक उल्लेख किया गया था। यह भी तर्क दिया

गया कि चूंकि वे पहले प्रभावित नहीं हुए थे, इसलिए खुद को फंसाने का सवाल पहले नहीं उठा था।

अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित : 1. जब उप-किरायेदारी का अधिकार स्थापित करने की मांग की गई थी 10 मई, 1993 के एक समझौते पर, यह होना चाहिए था एकल न्यायाधीश कि उप-किरायेदारी का ऐसा सृजन स्पष्ट रूप से उल्लंघनकारी था यथास्थिति का आदेश 15 सितंबर, 1988 को पारित किया गया था। [425- एफ]

2. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एकल न्यायाधीश ने परवाह भी नहीं की थी विचार प्रदान करना और एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर एक मौखिक आवेदन का मनोरंजन करना जिसका तब तक अवमानना के आवेदन से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने खुद को एक पक्ष के रूप में पेश करने के लिए एक आवेदन भी नहीं लिया था। यदि केवल मौखिक उल्लेख एक विशेष अधिकारी को हटाने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त हो सकता है बंद, किसी को प्रक्रिया के कानून को पूरी तरह से अलग करना होगा और न्याय प्रदान करना होगा जैसा कि अदालत सोचती है, उन पक्षों को आशीर्वाद प्रदान करती है जो 415 कर सकते हैं।

3. जब दायर की गई अपील में ताला हटाने की शिकायत की गई थी एतः अपीलकर्तासभ द्वारा विचित्र रूपसँ अधिकारक वितरणक आदेश देल

गेल छल। उक्त आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के दायरे के बारे में समझ की कमी को दर्शाता है और तथ्यों की पूरी तरह से गलत सराहना पर आगे बढ़ता है। एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ दोनों ने खुद को अवमानना क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं रखा था। इसके बजाय अजीबोगरीब आदेश इस मुद्दे के लिए पूरी तरह से अलग और तथ्यों की अवहेलना करते हुए पारित किए गए हैं। [426 - एच; 427-ए]

4. यह नहीं कहा जा सकता है कि संपत्ति को उप-पट्टे पर देने पर रोक थी यथास्थिति आदेश की शर्तों के तहत। इसका प्रभाव संपत्ति की स्थिति के संरक्षण का उल्लंघन करने का होता है। यह तब और भी अधिक होगा जब यह अदालत की अनुमति के बिना स्थिति को बिगाड़ने के लिए किया गया था जैसा कि वे तब थे। यह आदेश का उल्लंघन होगा। उक्ति में निहित सिद्धांत: ' एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट 'का इस मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करते हुए एक उप-किरायेदारी बनाई गई है। समान रूप से, यह तर्क कि एक अतिक्रमणकारी को भी कानून का सहारा लिए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता है, बिना किसी योग्यता के है। क्योंकि 15.9.1988 पर संपत्ति के संबंध में मामलों की स्थिति वही है जिससे न्यायालय का संबंध है। इस तरह के आदेश को दंड से मुक्त पक्षों द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता है और अदालत से अपना आशीर्वाद देने की उम्मीद की जा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवमानना की कार्यवाही में बिल्डर पक्षकार

नहीं थे। यह उन पक्षों के अधिकारों के अपमान में लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, जो मूल रूप से मुकदमा कर रहे थे। यदि उप-किरायेदारी के अधिकार को मान्यता दी जाती है, तो 15.9.1988 की यथास्थिति बनाए नहीं रखी जा सकती है। इसलिए, उप-पट्टा का अनुदान यथास्थिति के आदेश के विपरीत है जो स्पष्ट रूप से अवैध है। उप-पट्टा देने सहित सभी कार्य स्पष्ट रूप से अवैध हैं। [427- सी-एफ]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, [1987] पूरक। एससी. सी. पृष्ठ 394 398 पर, भरोसा किया।

5. दलों को 15.9.1988 के रूप में पद पर हटा दिया जाता है। द. प्रतिवादी बिल्डरों को खाली कब्जा देने का निर्देश दिया जाता है आज से एक महीने के भीतर विशेष अधिकारी। एकल न्यायाधीश को अवमानना के लिए आवेदन को अपने उचित परिप्रेक्ष्य में निपटाने का निर्देश दिया जाता है ताकि वह खुद को अवमानना क्षेत्राधिकार के लिए दंडित कर सके। अवमानना कार्यवाही के निपटारे तक विशेष अधिकारी अपने कब्जे में रहेगा। [427- एच; 428-ए] [1994] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 416 सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 449 ऑफ 1994 .

कलकत्ता उच्च न्यायालय के 5.10.1993 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ए. नं. में न्यायालय। 1993 का एन. आई. एल.

डॉ. शंकर घोष, एम. एल. चटर्जी, एम. सी. डींगरा और एस. के. बिस्वास

अपीलार्थियों के लिए।

पी. चिदंबरम, एस. के. जैन, ए. पी. धमीजा, राज कुमार गुप्ता और उत्तरदाताओं के लिए पी. सी. कपूर।

न्यायालय का निर्णय मोहन, जे. द्वारा सुनाया गया-अवकाश स्वीकृत।

1. इस अपील से जुड़े संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

विवादित परिसर एक चर्च की संपत्ति है नंबर 16 सडर स्ट्रीट, आउटहाउस सहित कलकत्ता। प्रथम प्रतिवादी कल्याण कुमार किस्कू ने दायर किया अपनी क्षमता में स्वामित्व की घोषणा के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 1988 का एक मुकदमा संख्या 328 दुर्गापुर सूबा के सचिव के रूप में। उक्त मुकदमे में यह दावा किया गया था कि इसमें दुर्गापुर सूबा शामिल है तीन कमरे और अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया गया कि दुर्गापुर सूबा के कब्जे को परेशान नहीं किया जा सकता है। यह मुकदमा उत्तर भारत के चर्च और दुर्गापुर सूबा के खिलाफ निर्देशित किया गया था।

उक्त मुकदमे में प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं:

"(ए) यह घोषणा करते हुए एक डिक्री पारित की जाए कि परिसर नं. 16, सडर स्ट्रीट, कलकत्ता 16 जिसमें आउटहाउस और गैरेज शामिल हैं जिसमें दुर्गापुर सूबा स्थित है कब्जा और/या कब्जा, दुर्गापुर के उक्त सूबा का है, जो कि सूबा को छोड़कर है अकेले कलकत्ता और दुर्गापुर सूबा के पास इसका उपयोग करने और आनंद लेने का कार्यकारी अधिकार और शीर्षक है;

(बी) यह घोषित करते हुए एक डिक्री पारित की जाए कि जब तक दुर्गापुर सूबा की संपत्तियों का सीमांकन नहीं किया जाता है और/या सीएनआई धर्मसभा के संकल्प के अनुसार स्थानांतरित और/या दुर्गापुर सूबा को सौंप दिया गया कलकत्ता सूबा से, कलकत्ता सूबा ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा निष्पादित वकील की शक्ति दुर्गापुर डायसिस के पक्ष में एसोसिएशन को बहाल किया जाए और दुर्गापुर डायसिस को कानूनी रूप दिया जाए दुर्गापुर के उक्त सूबा से संबंधित संपत्तियों के सभी किराए, मुद्दे और मुनाफे को इकट्ठा करने का हकदार;

(सी) यह घोषित करते हुए एक डिक्री पारित की जाए कि सीएनआई धर्मसभा के पदाधिकारियों के पास तारीख बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है एपिस्कोपल चुनाव आयोजित करने और ऐसे चुनाव कराने में किसी भी देरी की स्थिति में उक्त सी.एन.आई धर्मसभा के पदाधिकारियों के पास मॉडरेटर कमिशनरी और/या एपिस्कोपल नियुक्त करने का कोई अधिकार और/या



अधिकार नहीं है कमिश्नरी और कार्यकारी समिति के साथ-साथ दुर्गापुर की डायोसेसन काउंसिल भी नहीं हो सकती उक्त परिषद और कार्यकारी समिति को भंग कर दिया गया और/या अतिक्रमित कर दिया गया और/या भंग कर दिया गया अपने पूरे कार्यकाल, यानी 8 सितंबर, 1989 तक कार्य करने की अनुमति दी जाएगी;

(डी) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश (1) नियम 8 के तहत छुट्टी देने का आदेश पारित किया जाए;

(ई) पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने तक, यानी 8 सितंबर, 1989 तक प्रतिवादियों को डायोसेसन काउंसिल के साथ-साथ दुर्गापुर डायोसीज़ की कार्यकारी समिति के कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए;

(एफ) प्रतिवादियों और उनके नौकरों और एजेंटों को दुर्गापुर सूबा द्वारा आउटहाउस और गैरेज सहित नंबर 16, सडर स्ट्रीट, कलकत्ता 16 के परिसर के शांतिपूर्ण कब्जे और उपयोग और कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए;

(जी) प्रतिवादियों और उनके नौकरों और एजेंटों को सीएनआई धर्मसभा संकल्प के संदर्भ में और निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के संचालन द्वारा दुर्गापुर सूबा से संबंधित संपत्तियों का किराया, मुद्दे और/या मुनाफा इकट्ठा करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए।

या कलकत्ता डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन द्वारा तब तक निष्पादित किया जाएगा जब तक कि दुर्गापुर डायोसीज़ से संबंधित संपत्तियों को कलकत्ता डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन (निजी) द्वारा दुर्गापुर डायोसीज़ को सौंप नहीं दिया 5. 20 जुलाई, 1993 के एक आदेश द्वारा अदालत ने सूट परिसर की पहली मंजिल पर स्थित कमरों की एक सूची बनाने और यह भी पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या वहां कोई ताला लगा था। उस आदेश के तहत विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी. सूची तैयार होने के बाद उसे ताला तोड़ने और अपना ताला लगाने की अनुमति दी गई। 6. 4 अगस्त, 1993 को विशेष अधिकारी को जांच जारी रखने और 26 जुलाई, 1993 के आदेश के अनुसार इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया था। मुख्य दरवाजे की चाबियाँ प्रभारी अधिकारी, तालटोला पुलिस स्टेशन के पास रहेंगी।

7. 16 अगस्त, 1993 को 26 जुलाई, 1993 के उक्त आदेश को इस आशय से संशोधित किया गया कि रिसीवर पहले के आदेश के अनुसार वस्तुओं की सूची बनाएगा, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला नहीं लगाएगा। 16 अगस्त 1993 के उक्त आदेश में इस आशय का संशोधन करने की मांग की गई थी कि विशेष अधिकारी को प्रत्येक पक्ष के प्रतिनिधियों को अनुमति देनी चाहिए और सूची बनाते समय कब्जाधारियों में से किसी को भी अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया. इससे पहले तक, सोमानी बिल्डर्स (यहां प्रतिवादी 2) किसी

भी कार्यवाही में पक्षकार नहीं था और न ही उसने खुद को पक्षकार बनाने के लिए कोई आवेदन दायर किया था। फिर भी सोमानी बिल्डर्स द्वारा की गई मौखिक प्रार्थना को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर 20 अगस्त 1993 को अनुमति दी गई:

"श्री घोष द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इन्वेंट्री पूरी होने के बाद भी रिसीवर ने ताला लगा दिया है। श्री भट्टाचार्य, विद्वान रिसीवर मौजूद हैं। रिसीवर द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इन्वेंट्री पूरी हो गई है। रिसीवर को ताला हटाने का निर्देश दिया गया है, यदि कोई हो, कल तक उसके द्वारा डाल दिया जाएगा।"

8. इन कार्यवाहियों से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं द्वारा अपील दायर की गई। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि उक्त ए.के. घोष न तो किरायेदार थे और न ही उनके पास परिसर के किसी भी हिस्से को किराए पर देने की क्षमता या अधिकार था। अतः उक्त ए.के. घोष को किरायेदार के रूप में वहां रहने का अधिकार नहीं था। आगे यह आग्रह किया गया कि किरायेदारी का निर्माण एक बाद का विचार था और उक्त सोमानी बिल्डर्स के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था जिन्होंने इस कार्यवाही में हस्तक्षेप किया था। इस याचिका पर अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार टिप्पणी की:

"चाहे सोमानी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड हो या नहीं।"

इस कार्यवाही में एक वैध उप-किरायेदार का निर्णय नहीं किया जा सकता है। यह मकान मालिक पर निर्भर है कि वह उन्हें बेदखल करने के लिए उचित कार्यवाही शुरू करे। लेकिन इस स्तर पर, सवाल यह है कि क्या सोमानी बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड का कब्जा है या नहीं। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि कंपनी का विवादित परिसर पर कब्जा था। यहां तक कि किसी अतिक्रमणकारी को भी उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बेदखल किया जा सकता है।"

9. इसके बाद यह तालटोला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से चाबियां प्राप्त करने के निर्देश के साथ संयुक्त रिसीवर नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ा। वे उन कमरों की सूची बनाएंगे जिन पर सोमानी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का कब्जा बताया गया है। लिमिटेड ताला खोल रहा है जिसे विशेष अधिकारी द्वारा ठीक किया गया था। सूची बनाने के बाद संयुक्त रिसीवर को उक्त परिसर पर कब्जा लेने का निर्देश दिया गया। उन्हें सोमानी बिल्डर्स को सामान्य रूप से व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से उक्त परिसर पर कब्जा करने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया गया था। पार्टियों के अधिकारों और विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सोमानी बिल्डर्स द्वारा संयुक्त रिसीवर्स को कब्जा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

10. इन परिस्थितियों में विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान सिविल अपील को प्राथमिकता दी जाने लगी है। अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है कि दुर्गापुर सूबा के कब्जे में अचल संपत्ति के संबंध में 15 सितंबर, 1988 के यथास्थिति आदेश के मद्देनजर कोई किरायेदारी या उप-किरायेदारी अधिकार नहीं बनाया जा सकता है। यह भी आग्रह किया गया कि उक्त सोमानी बिल्डर्स 10 मई, 1993 के एक समझौते के तहत उप-किरायेदार बन गया। यथास्थिति आदेश के मद्देनजर ऐसी उपकिरायेदारी वैध नहीं हो सकती। यह कुछ अजीब है कि सोमानी बिल्डर्स को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष मौखिक आवेदन करना पड़ा। उस मौखिक आवेदन के आधार पर, सोमानी बिल्डर्स के पक्ष में आदेश पारित किया गया जिसमें विशेष अधिकारी को ताला हटाने का निर्देश दिया गया। प्रार्थना की प्रकृति क्या थी, वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इन कार्यवाही में किसी का भी पक्षकार नहीं था, ज्ञात नहीं है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशानुसार, उसके कहने पर ताला हटाना उचित नहीं था। जब अपीलकर्ता इस आदेश के बारे में शिकायत कर रहा था, तो डिवीजन बेंच ने एक कदम आगे बढ़कर सोमानी बिल्डर्स को कब्जा देने का निर्देश दिया। यह निर्देश पूर्व कथित किरायेदार ए.के. द्वारा की गई अवैधता पर प्रीमियम लगाने जैसा होगा। घोष.

11. सबसे पहले, उसके पास किरायेदारी देने का कोई अधिकार नहीं था। अन्यथा भी, चूंकि 15 सितंबर 1988 को न्यायालय द्वारा यथास्थिति

आदेश पारित किया गया था, इसलिए 10 मई 1993 के समझौते के तहत उप-किरायेदारी का निर्माण सोमानी बिल्डर्स को कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेगा। अवमानना क्षेत्राधिकार में कार्यवाही के लिए पूरी तरह से अजनबी को कब्जे में नहीं लिया जा सकता है, जबकि एकमात्र सवाल यह था कि क्या पार्टियों ने 15 सितंबर, 1988 के आदेश का उल्लंघन किया था। इसलिए, आदेश रद्द किया जाने योग्य है।

12. प्रतिवादी 1 के विद्वान वकील कल्याण कुमार किस्कू ने प्रस्तुत किया:

"यहाँ अपीलकर्ता पूरी तरह से जानते हैं कि वे प्रतिवादी 1 द्वारा दायर मुकदमे में सफल नहीं हो सकते हैं और इसलिए, उन्होंने अवैध और अनुचित तरीके अपनाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक छोटा रास्ता अपनाया है, जिससे पहली मंजिल के सभी रहने वालों को बेदखल कर दिया गया है। कानून की मंजूरी.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि सामान्य कानूनी अर्थ के अनुसार, यथास्थिति शब्द किसी भी समय पर चीजों की मौजूदा स्थिति को दर्शाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त 'यथास्थिति' की परिभाषा के मद्देनजर, दुर्गापुर डायोसीज़, डायोसेसन काउंसिल की कार्यकारी समिति

के कामकाज सहित अपनी गतिविधियों को चलाने के संबंध में 20 मई, 1988 को अपनी मौजूदा गतिविधियों को जारी रखने का हकदार था।

व्यवहारिक तौर पर यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अंतरिम आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करता है। निर्भरता दो निर्णयों पर रखी गई है: (i) आंध्र प्रदेश राज्य बनाम टी. आनंदगोपाल 2, (ii) महाराष्ट्र राज्य बनाम दादामिया बाबूमिया शेख 3।"

13. प्रतिवादी-किरायेदार के लिए विद्वान वकील, ए.के. घोष ने आग्रह किया कि वह 1988 से परिसर के किरायेदार थे। उन्हें उपपट्टा देने के लिए 11 मार्च 1988 के दुर्गापुर सूबा के एक प्रस्ताव द्वारा उप-किरायेदारी बनाने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया गया था। यथास्थिति का आदेश उन पक्षों के विरुद्ध था जिन्हें अंतर्वर्ती आवेदन में पक्षकार बनाया गया था।

14. सोमानी बिल्डर्स के विद्वान वकील श्री पी.चिदंबरम प्रस्तुत करेंगे कि अवमानना के लिए आवेदन उसमें उत्तरदाताओं के खिलाफ निर्देशित किया गया था। जहां, इसलिए, उन्हें यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था, किरायेदार ए.के. की ओर से कोई कानूनी विकलांगता नहीं थी। घोष ने संपत्ति को उप-किराए पर देने का आदेश दिया। इसलिए, यदि उप-किरायेदार को कानूनी रूप से शामिल किया गया था तो वह कानूनी रूप से परिसर के कब्जे में रह सकता है क्योंकि इसे

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संयुक्त रिसीवर को सौंपने का निर्देश दिया गया था। सोमानी बिल्डर्स की ओर से विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख करना आवश्यक हो गया क्योंकि इसके कब्जे को विशेष अधिकारी 1 1987 सप्प एससीसी 394 2 1986 सप एससीसी 568 3 (1972) 3 एससीसी 85: 1972 एससीसी (सीआरआई) द्वारा परेशान किया गया था। ) 405 ताला ठीक करना। तब तक खुद को पक्षकार बनाने का सवाल ही नहीं उठता था. केवल जब यह प्रभावित होता था तो मौखिक उल्लेख करना पड़ता था। अपीलिय अदालत ने पाया कि कब्जे में गड़बड़ी हुई थी जिसे सोमानी बिल्डर्स को वापस कर दिया गया। जितनी इन्वेंट्री का खुलासा हुआ, उसकी संपत्तियां परिसर में पाई गईं। लिखित प्रस्तुतियाँ में, यह आगे आग्रह किया गया है:

"एक्टस क्यूरीए नेमिनेम ग्रेवबिट का अर्थ है कि न्यायालय का कोई भी कार्य किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा:

(ए) कानून के इस सिद्धांत को अंग्रेजी न्यायालयों के साथ-साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी लागू किया गया है। (अलेक्जेंडर रॉजर, चार्ल्स कार्नी और रिचर्ड जेम्स गिलमैन बनाम द कॉम्पोटोइर डी'एस्कोम्प्टे डी पेरिस और द चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन 4, जगत धीश भार्गव बनाम जवाहर लाल भार्गव 5 और जंग सिंह बनाम बृज लाल 6 देखें।



(बी) जगत धीश भार्गव बनाम जवाहर लाल भार्गव मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 'मुकदमाकर्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अदालत या उसके अधिकारियों द्वारा की गई चूक या दिखाई गई लापरवाही के खिलाफ सुरक्षा का हकदार है।' एक अवमानना कार्यवाही में, जो प्रतिवादी 2 या उसके किसी भी अधिकारी के खिलाफ शुरू भी नहीं की गई थी, उक्त प्रतिवादी को बेदखल कर दिया गया था:

(ए) न्यायालय के पास अवमानना कार्यवाही में किसी को बेदखल करने का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न तो न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 और न ही अनुच्छेद 215 न्यायालय को अवमानना कार्यवाही में बेदखली का कोई आदेश पारित करने के लिए अधिकृत करता है;

(बी) किसी भी घटना में, अवमानना की कार्यवाही में, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, जो उसमें पक्षकार नहीं है, कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और उसे कोई नोटिस दिए बिना और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना। (न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 14 देखें);

(सी) उक्त अवमानना याचिका प्रतिवादी 1 द्वारा कुछ विशेष अवकाश याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि

विशेष अवकाश याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है।

(डी) इसलिए, अदालत के पास ऐसी कार्यवाही में प्रतिवादी 2 के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

मुकदमे में पारित कोई भी आदेश किसी ऐसे व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता, जो उसमें पक्षकार नहीं था:

(ए) किरायेदार अशोक कुमार घोष और उनके उप-किरायेदार सोमानी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थापित मुकदमे में पक्षकार नहीं थे। इसलिए, कोई भी आदेश 4 एलआर(1871)3 पीसी 465 5 एआईआर 1961 एससी 832: (1961) 2 एससीआर 918: (1961) 1 केर एलआर 437 6 एआईआर 1966 एससी 1631: (1964) 2 एससीआर 145: 65 पुंज एलआर 884 उक्त मुकदमे में पारित किया गया उनमें से किसी पर भी कभी भी बाध्यकारी था या है;

(बी) किरायेदार; 'मुकदमे की संस्था' से पहले शामिल किया गया था। मुकदमा '29 अप्रैल, 1988 को स्थापित किया गया था और उससे पहले, किरायेदार को इसमें शामिल किया गया था;

(सी) 20 मई 1988 को किरायेदार को उपकिरायेदारी देने के लिए अधिकृत किया गया था;

(डी) यह मुकदमा इस घोषणा के लिए था कि परिसर संख्या 16, सडर स्ट्रीट, कलकत्ता, इसके आउटहाउस और गैरेज सहित, दुर्गापुर के सूबा का है और दुर्गापुर के सूबा के पास इसका उपयोग करने का विशेष अधिकार, शीर्षक और हित है;

(ई) 20 मई 1988 को, मुकदमे के पक्षों को अगले आदेश तक दुर्गापुर सूबा के संचालन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था;

(एफ) 15 सितंबर 1988 को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दुर्गापुर सूबा की अचल संपत्तियों के संबंध में उक्त तिथि पर यथास्थिति का आदेश पारित किया;

(छ) उक्त आदेश किरायेदार अशोक कुमार घोष पर बाध्यकारी नहीं थे, न ही ऐसा होने का दावा किया जा सकता है;

(ज) किसी भी स्थिति में, 15 सितंबर 1988 को पारित यथास्थिति आदेश जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि इसे 15 सितंबर 1988 तक बनाए रखा जाना चाहिए, किरायेदार के अधिकार को कम नहीं कर सकता है, जो उसे 20 मई को दिया गया है। 1988;

(i) इस विनिर्देश के साथ यथास्थिति आदेश कि यह उस तिथि के अनुसार ही होना चाहिए, बिना किसी कल्पना के पूर्वव्यापी रूप से बढ़ाया या लागू नहीं किया जा सकता है;

(जे) इस प्रकार, 20 मई 1988 को उप-किरायेदारी देने का किरायेदार का अधिकार 15 सितंबर 1988 के यथास्थिति के उक्त आदेश से प्रभावित नहीं था और न ही प्रभावित हो सकता था।

इसलिए, आक्षेपित आदेश में कोई अपवाद नहीं लिया जाएगा।

15. संबंधित तर्कों की सराहना करने के लिए यह बताना आवश्यक है कि निम्नलिखित तीन आदेशों के उल्लंघन की शिकायत की गई थी:

(1) 20 मई 1988 (2) 1 जून 1988 (3) 15 सितम्बर 1988

16. जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम दो आदेशों में से पहले से चिंतित नहीं हैं क्योंकि वे संपत्ति से संबंधित नहीं हैं। यह 15 सितंबर 1988 (पहले से निकाले गए) आदेश का उल्लंघन है जो अवमानना को जन्म देता है। अवमानना मुख्य रूप से उत्तरदाताओं द्वारा 3 जुलाई, 1993 को सूट परिसर के प्रवेश द्वार पर ताला लगाने, पहली मंजिल के लिए पानी की आपूर्ति बंद करने और सीवरेज आदि को अवरुद्ध करने के बारे में थी। इसलिए, यह तय करने की आवश्यकता थी कि क्या उत्तरदाताओं ने इसमें बनाए रखा था यथास्थिति है या नहीं। यदि किसी भी प्रकार की अवज्ञा होती तो वह अवमानना मानी जाती। इस प्रकार, यह अवमानना का एक साधारण मामला है। दुर्भाग्य से, इसने एक कुटिल रास्ता अपना लिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों द्वारा अजीबोगरीब आदेश पारित किए गए हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26 जुलाई 1993 के

आदेश द्वारा विशेष अधिकारी को मामलों की स्थिति की एक सूची बनाने का निर्देश दिया। अवमानना की याचिका में कथित उल्लंघन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए चीजों की सूची बनाने की जरूरत कहाँ थी, यह समझना मुश्किल है। सामान लेने के बाद विशेष अधिकारी ने अपना ताला लगा दिया था। यह मुख्य प्रवेश द्वार था या नहीं यह एक सहायक मुद्दा था। इसी चरण में सोमानी बिल्डर्स ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। इसने ताला हटाने के लिए मौखिक आवेदन किया। प्रार्थना का स्वरूप क्या था, यह कहीं भी समझ में नहीं आता। विद्वान न्यायाधीश के आदेश में भी इस प्रार्थना का उल्लेख नहीं है। यह सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए कि सोमानी बिल्डर्स ने अपना दावा 10 मई, 1993 के समझौते के आधार पर किया था, जिसमें ए.के. से उप-किरायेदारी के अधिकार का दावा किया गया था। घोष.

17. सबसे पहले, क्या ए.के. घोष के किराएदार होने का मामला खुद विवादों में है। दूसरे, क्या ए.के. घोष को उप-किरायेदारी बनाने का अधिकार एक बार फिर विवाद में है। तीसरा, इन सबसे बढ़कर, जब 10 मई, 1993 के एक समझौते पर उप-किरायेदारी का अधिकार स्थापित करने की मांग की गई थी, तो विद्वान एकल न्यायाधीश को यह विचार करना चाहिए था कि उप-किरायेदारी का ऐसा निर्माण स्पष्ट रूप से उल्लंघनकारी था। यथास्थिति का आदेश 15 सितंबर, 1988 को ही पारित कर दिया गया था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्वान न्यायाधीश ने एक विचार देने की भी

परवाह नहीं की और एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर मौखिक आवेदन पर विचार किया, जिसका उस समय तक इससे कोई लेना-देना नहीं था। अवमानना के लिए आवेदन. उन्होंने खुद को पक्षकार बनाने के लिए कोई आवेदन भी नहीं दिया था। यदि केवल मौखिक उल्लेख किसी विशेष अधिकारी को ताला हटाने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त हो सकता है, तो किसी को प्रक्रिया के कानून को पूरी तरह से अलग रखना होगा और अदालत की कल्पना के अनुसार न्याय प्रदान करना होगा, उन पक्षों को आशीर्वाद देना होगा जिनके पास अपने दावे को पूरा करने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं हो सकता है।

18. आगे तो और भी बुरा हाल था. जब हमारे सामने अपीलकर्ताओं ने ताला हटाने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निर्देश की शिकायत की, तो डिवीजन बेंच ने एक नई प्रक्रिया का पालन किया। हम उप-किरायेदारी की वैधता के संबंध में इसका निष्कर्ष पहले ही निकाल चुके हैं। सोमानी बिल्डर्स वैध रूप से उप-किरायेदार है या नहीं, यह अनिश्चित शर्तों पर होने के कारण कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे सोमानी बिल्डर्स की याचिका को खारिज कर देना चाहिए था। फिर संयुक्त रिसीवरों को सोमानी बिल्डर्स को व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से परिसर पर कब्जा करने की अनुमति देने का निर्देश क्यों दिया गया, यह हमारी समझ से परे है? यथास्थिति इन्वेंट्री की तारीख पर यथास्थिति नहीं है, बल्कि 15 सितंबर, 1988 की यथास्थिति है। उस तारीख का आदेश

स्पष्ट रूप से "आज की यथास्थिति" बताता है। इसका मतलब केवल 15 सितंबर, 1988 हो सकता है और उस आदेश के पांच साल बाद की स्थिति नहीं हो सकती।

19. व्हार्टन लॉ लेक्सिकन में, 14वाँ संस्करण। पी पर 95 1, यथास्थिति को इस अर्थ में परिभाषित किया गया है:

" किसी भी तारीख पर चीजों की मौजूदा स्थिति; उदाहरण के लिए, यथास्थिति, युद्ध से पहले की चीजों की स्थिति।"

20. ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, छठा संस्करण। प्रासंगिक मार्ग होता है:

" किसी भी तारीख पर चीजों की मौजूदा स्थिति। यथास्थिति, युद्ध से पहले की स्थिति। प्रारंभिक निषेधाज्ञा द्वारा संरक्षित की जाने वाली 'यथास्थिति' अंतिम वास्तविक, शांतिपूर्ण, निर्विरोध स्थिति है जो लंबित विवाद से पहले थी।"

21. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम बिहार राज्य' में इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा: (एससीसी पृष्ठ 398, पैरा 5) "सामान्य कानूनी अर्थ के अनुसार, यथास्थिति' शब्द किसी भी समय चीजों की मौजूदा स्थिति को दर्शाता है इस समय पर।"

22. जब यहां अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील में ताला हटाने की शिकायत की गई, तो अजीब तरह से कब्जा देने का आदेश दिया गया! उक्त आदेश स्पष्ट रूप से अवमानना क्षेत्राधिकार के दायरे के बारे में समझ की कमी को दर्शाता है और तथ्यों की पूरी तरह से गलत व्याख्या पर आगे बढ़ता है। हम यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों ने खुद को अवमानना क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं रखा था। इसके बजाय मुद्दे से पूरी तरह अलग और तथ्यों की उपेक्षा करते हुए अजीबोगरीब आदेश पारित किए जाने लगे हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्डपीठ के आदेश एक क्षण की भी जांच में टिक नहीं सकते। इसलिए, यह तर्क देना बेकार है कि अनुच्छेद 136 के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

23. इस तथ्य के अलावा कि क्या ए.के. घोष के पास उपपट्टा देने का कानूनी अधिकार था या नहीं, आदेश का उल्लंघन करते हुए उपपट्टा देना उनके लिए खुला नहीं था। यह तर्क देने का कोई फायदा नहीं है, जैसा कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री चिदम्बरम का कहना है कि यथास्थिति आदेश की शर्तों के तहत इस तरह के उपपट्टे पर रोक थी। इसका प्रभाव संपत्ति की स्थिति के संरक्षण का उल्लंघन करना है। यह तब और भी अधिक होगा जब यह अदालत की अनुमति के बिना तत्कालीन स्थिति को बिगाड़ने के लिए किया जाएगा। यह आदेश का उल्लंघन होगा। कहावत 'एक्टस क्यूरिया नेमिनेम ग्रेवाबिट' में निहित सिद्धांत का इस



मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है जब यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करते हुए एक उप-किरायेदारी बनाई गई है। समान रूप से, यह तर्क कि किसी अतिचारी को भी कानून का सहारा लिए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता, निराधार है, क्योंकि 15 सितंबर, 1988 को संपत्ति के संबंध में मामलों की स्थिति से अदालत चिंतित है। इस तरह के आदेश को उन पक्षों द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता है जो दण्ड से मुक्त हैं और उम्मीद करते हैं कि अदालत अपना आशीर्वाद देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवमानना कार्यवाही में सोमानी बिल्डर्स एक पक्ष नहीं था। यह उन पक्षों के अधिकारों के हनन में लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, जो मूल रूप से मुकदमा कर रहे थे। यदि उपकिरायेदारी के अधिकार को मान्यता दी गई है, तो 15 सितंबर 1988 की यथास्थिति कैसे बनाए रखी जाती है? अतः उपपट्टा प्रदान करना यथास्थिति के आदेश के विपरीत है। यथास्थिति के आदेश के तहत किया गया कोई भी कार्य स्पष्ट रूप से अवैध है। उपपट्टा देने सहित सभी कार्य स्पष्ट रूप से अवैध हैं।

24. हमने इसके द्वारा डिवीजन बेंच के 5 अक्टूबर 1993 के आदेश और 20 जुलाई 1993 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश (विशेष अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भाग को छोड़कर), 4 अगस्त 1993, 6 अगस्त को रद्द कर दिया। 1993, 11 अगस्त 1993, 16 अगस्त 1993 और 20 अगस्त 1993 भी।

25. पार्टियों को 15 सितंबर 1988 की स्थिति में वापस कर दिया गया है। सोमानी बिल्डर्स को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से एक महीने के भीतर विशेष अधिकारी को खाली कब्जा सौंप दें। विद्वान एकल न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है कि वह स्वयं को अवमानना क्षेत्राधिकार तक सीमित रखते हुए अवमानना के आवेदन का उचित परिप्रेक्ष्य में निपटान करें। अवमानना कार्यवाही के निपटारे तक विशेष अधिकारी का कब्जा बना रहेगा। कब्जे की होड़ को देखते हुए यह निर्देश जरूरी हो जाता है।

26. उपरोक्त कारणों से, सिविल अपील को उन लागतों के साथ अनुमति दी जाती है जो इस अपील में उत्तरदाताओं 1 और 2 द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी सुश्री कुसुम मीणा, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकारान को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।